

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सु0प्र0उ0ज0 (सतर्कता) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 24 जून, 2016।

विषय: गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता के आरोप में अभियोजन दायर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने सम्बन्धी समस्त प्रकरणों पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है, जिसके निर्वचन से यह स्पष्ट होता है कि केवल "लोक सेवकों" के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु सम्बन्धित "नियुक्ति प्राधिकारी या लोक सेवक को पद से हटाये जाने हेतु "सक्षम प्राधिकारी" की अनुमति आवश्यक है।

2. उक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक नहीं है तथा उसकी किसी लोक सेवक के साथ भ्रष्टाचार या अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित हो रही है, के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन एवं सतर्कता अधिष्ठान के मध्य होने वाले पत्राचार में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता के आरोप में मा0 न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने हेतु पर्याप्त एवं पुष्ट साक्ष्य होने के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के विधि परामर्शी द्वारा पुष्टि की जाती है तो उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में अभियोजन दायर करने हेतु निदेशक, सतर्कता को अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिनमें व्यक्ति कभी सरकारी सेवक रहा हो और सेवा काल के कृत्यों के निष्पादन में कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरण में अभियोजन चलाया जाना आवश्यक हो तो प्रकरण शासन को अवश्य ही सन्दर्भित किये जायेंगे तथा अग्रेत्तर कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार ही सम्पादित की जाएगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेशों को असंगति की सीमा तक अवक्रमित समझा जाये।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
प्रभारी सचिव।

जारी करें
24/6/2016